

## एक नजर

डीजल चोर गिरोह का पर्दाफाश



भारतीय बस्ती संवाददाता- बस्ती। पुलिस ने एक अंतरजन्मदीय डीजल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 25 हजार रुपये के इनामी अपराधी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से घोरों में इस्तेमाल होने वाले ऑइलर, लगभग 100 लीटर चोरी का डीजल, नकदी, बनावट फोन और एक चार पहिया वाहन बरामद किया है।

पुलिस के अनुसार, शनिवार को पच्छिमपुर तिराहा सर्किट लेन के पास चेन्नई के बंदरान इन तीनों सदियों को पकड़ा गया। पूरासाथ में आरोपियों ने बताया कि वे किंगपुर के चार पहिया वाहन से विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर ट्रक और ट्रैक्टर की टैंकों के ताले तोड़कर डीजल चोरी करते थे। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर छानबीन थाने में नुकसान दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया।

गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान भीम पाण्डेय (पुत्र शिवतल प्रसाद पाण्डेय, निवासी मुस्तफाबाद, थाना अहिरौली, जनपद अंबेडकरनगर), 6 फीट गोस्वामी (पुत्र सत्यनारायण का पुरवा, थाना देवहिनपुर, जनपद अंबेडकरनगर) और मोहन पाण्डेय (पुत्र जालंधर पाण्डेय, निवासी मुस्तफाबाद, थाना अहिरौली, जनपद अंबेडकरनगर) के रूप में हुई है। भीम पाण्डेय पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। बरामद सामान में तीन पिस्तौल, तीन बड़े स्मॉल आर्म्स, एक हॉन्डा सिटी कार और लगभग 100 लीटर चोरी का डीजल शामिल है। इस कारवाई में न्यायाध्यक्ष बरामद, स्वातंत्र्यसैनिक प्रमोदी शोभनथ यादव सहित छानबीन थाना, एसओजी, स्वातंत्र्य और सिलेंस टीम के कई पुलिसकर्मी शामिल रहे।

अस्पताल पर 5.30 लाख का जुर्माना

भारतीय बस्ती संवाददाता- बस्ती। जिला उपनिष्ठा कोष में एक निजी अस्पताल को गंभीरता महिषा के अपराध में गंभीर लम्परवाही बरतने का दोषी ठहराया है। कोष में अस्पताल प्रबंधकों के 5.30 लाख रुपये का जुर्माना करने का आदेश दिया है। इसमें भीष्माटा का चार लाख रुपये उधार ब्याज और 1.30 लाख रुपये मानसिक व आर्थिक नुकसान के मुआवजे के रूप में देने के निर्देश शामिल हैं। मामले की सुनवाई जिला उपनिष्ठा कोष के अध्यक्ष विद्यालक्ष्मी अमरजीत वर्मा और सदस्य अरुण प्रकाश सिंह ने की।

यह परिवार मुख्यतः थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव निवासी रिपटी पत्नी कृष्णा ने अशिक्षित शिव कुमार रिपटी की माध्यम से दाखिल किया था। परिवार के अनुसार, सारिता को प्रसव के लिए 14 अगस्त 2021 को राहल स्थित रमणनाथ शुकला एम्स.स. मेंकेंद्र सेंटर में भर्ती कराया गया था। उसी दिन ऑपरेशन के जरिए बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन नवजात ने कुछ ही देर बाद दम तोड़ दिया। महिषा को 23 अगस्त को अस्पताल से छुड़ी दे दी गई थी।

भीष्माटा ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन के बाद से ही उसके पेट और नाभि के आसपास लगातार अहमती दर्द बना रहा। अस्पताल के चिकित्सकों सहित कई अन्य डॉक्टरों से उपचार और जांच कराने के बावजूद उसे राहत नहीं मिली। बाद में डॉक्टर विनायक पर सारिता को पेट में भर्ती कराया गया। बाद 18 दिसंबर 2021 को हुए ऑपरेशन में महिषा के पेट से सौतेला का एक टुकड़ा निकाला गया। एम्स की चिकित्सकीय टीम ने भी कई ऑपरेशन में लम्परवाही का उल्लेख किया गया है। मामले में अस्पताल प्रबंधन के लापरवाही से इन्कार किया था। हालांकि, दोनों भाई की दलीलें सुनने के बाद कोष ने अस्पताल प्रबंधकों को दोषी ठहराते हुए पीडिता के खर्च में फैसला सुनाया।

## जमीन-जायदाद के लंबित मामलों पर मुख्यमंत्री योगी सख्त, तय होगी अफसरों की जिम्मेदारी



लखनऊ (आभा)। योगी ने जमीन-जायदाद से जुड़े मुद्दों के लंबित मामलों पर सीएम योगी ने सख्त दिखाई है। राजस्व मामलों की समीक्षा कर रहे सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा, राजस्व मामलों के त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि और राजस्व से जुड़े विवाद आमजन के जीवन, किसान हितों और समाजिक सौहार्द से सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए इन मामलों में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्धारित समय-सीमा के बाद भी लंबित रहने वाले मामलों में संबंधित अधिकारियों और कार्मिकों की जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। शनिवार को राजस्व न्यायालयों

## भौषण गर्मी में बेजुबानों के लिए राहत बनी ग्राम पंचायत मरहा की पहल



भारतीय बस्ती संवाददाता- बस्ती। भौषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच जहां इंसान गर्मी से बेहाल हैं, वहीं बेजुबान पशु-पक्षियों के सामने भी पानी का कंठिभर खड़ा हो गया है। ऐसे कठिन समय में जनपद बस्ती के सदर विकासखंड के ग्राम पंचायत मरहा ने मानवता और जीव संरक्षण की मिसाल पेश करते हुए पंचायत क्षेत्र के विभिन्न सर्वजनिक, सुव्युत्त, एवं सुगम स्थलों पर पानी से भर नाद (जल पात्र) रखवाने की सराहनाएं पहल शुरू की है।

ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के परचमूमि में दर्जन भर स्थानों पर जल पात्र स्थापित किए गए हैं, ताकि अलावा पशु-पक्षियों, कुत्ते तथा पक्षियों को भीषण गर्मी में आसानी से पीने योग्य पानी उपलब्ध रहे। पंचायत की इस पहल की ग्रामीणों द्वारा सख्त सराहना की जा रही है। प्रमाण प्रतिलिपि अखिल कुमार यादव ने बताया कि गर्मी के मौसम में सबसे अधिक परेशानी बेजुबान जीवों को लिए राहत बनी है, बल्कि मानवता उछानी पड़ती है। कई बार पानी के

में लंबित वादों के निस्तारण की प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक आधारित व्यवस्था, जवाबदेही और समयबद्ध कार्यप्रणाली के माध्यम से राजस्व न्यायालयों की कार्यक्षमता को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, ताकि आम नागरिकों को शीघ्र न्याय मिल सके। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से निर्देश दिए कि निर्धारित समय-सीमा से अधिक अवधि से लंबित वादों का अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि तहसील और जनपद स्तर पर नियमित समीक्षा हो तब कमजोर प्रदर्शन करने वाले जिलों की जवाबदेही तय की जाए।

## विवादित जमीन में नाली निर्माण रोकने की मांग दवांगों ने पत्नी को मारा पीटा: छीन लिया मंगलसूत्र

भारतीय बस्ती संवाददाता- बस्ती। वाटररजि थाना क्षेत्र के बड़कुईया गांव में जमीनी विवाद में मार पीटा और रामकुश की पत्नी का मंगलसूत्र छीन लिये जाने का मामला सामने आया है। इस सम्बन्ध में रायबड़ पंचायत में वाटररजि पुलिस को लिखित सूचना देकर मामले में न्याय की गुहार लगाया है।

वाटररजि पुलिस को दिये पत्र में रामकुश ने कहा है कि ग्राम प्रधान राम सुभाष, राम जी, बिन्दावती देवी पत्नी धर्मराज, मीरा देवी पत्नी लालजी, प्रभा देवी पत्नी रामजी, रामजी पुत्र रामधियार व अन्य के बीच जमीनी विवाद चल रहा है। तथा उसी के संबंध में सिविल जज जूडिओ वाद सं 242 के मुद्दा लम्बित भी है फिर भी पिछली राम सुभाष व अन्य उसी विवादित जमीन में नाली निर्माण कारनावा बराह रहे हैं। 121 मी के रूप सुभाष व अन्य सहयोगियों ने विवादित जमीन पर धावा बोल दिया और उसकी पत्नी को मारा पीटा, गले में पहने हुये मंगलसूत्र को छीन ले गये। वाटररजि पुलिस इस प्रकरण में गत 11 फरवरी को 11/126.135 की कारवाही भी कर चुकी है फिर भी राम सुभाष व उनकी सहयोगी आदि आमदा फौजदारी हैं। रामकुश ने पत्नी के लोप गये मंगलसूत्र को दिलाने के साथ-साथ निर्माण कार्य रूकवाने की मांग किया।

## पूर्व विधायक अफसर यू अहमद के निधन से शोक की लहर



भारतीय बस्ती संवाददाता- बस्ती। पूर्व विधायक अफसर यू अहमद जी को लंबे समय से चल रहे इलाज के दौरान शुक्रवार को निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन की सूचना मिलते ही परजिन उनके पालिश शरीर को लेकर दरियावाड़ी स्थित आवास पहुंचे, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का ताता लग गया। संत कबीर नगर जिला कमेटी के जिलाध्यक्ष प्रवीण चंद्र पांडे, कांति

## अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक

नई दिल्ली (आभा)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ शनिवार को द्विपक्षीय बैठक की। यह मुलाकात नई दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ में हुई, जहां भारत-अमेरिकी संबंधों को और मजबूत बनाने व विभिन्न क्षेत्रों में



सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच सकारात्मक चर्चा हुई, जिसमें रणनीतिक सहकारिता, व्यापार, सुरक्षा और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ। मॉटिंग के अंत में रूबियो ने पीएम मोदी को वाइट हाउस आने का न्योता दिया।

## जनगणना ड्यूटी में अनियमितता के सवाल को लेकर दूसरे दिन भी जारी रहा शिक्षकों का धरना: आश्वासन पर माने शिक्षक

भारतीय बस्ती संवाददाता- बस्ती। जनगणना ड्यूटी में अनियमितता के सवाल को लेकर शिक्षकों का धरना उप जिलाधिकारी कार्यालय हर्षा के समक्ष दूसरे दिन शनिवार को भी जारी रहा। तहसीलदार हर्षा और सख्त शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया कि जितने भी आवेदन पत्र आए हैं उनका संशोधन शनिवार की राति में कर ड्यूटी की सूची मुद्रण पर भेज दी जाएगी। यदि किसी का तब भी गड़बड़ी रहती है तो खंड शिक्षा अधिकारी उसका संशोधन करा देंगे। इसी शर्त के साथ धरना स्थगित किया गया।



उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष उदयशंकर शुक्ल ने बताया कि धरना स्थल पर तहसीलदार हर्षा अमर राज और खंड शिक्षा अधिकारी प्रमोद श्रीवास्तव विजय आनंद और आए विस्तृत रूप से बातें हुई। अत्यापकों ने जनगणना की किट लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें नियुक्ति आदेश आईडी नजरी नरेशा सहित मानव और अतिरिक्त नहीं थे। धरने पर बैठे शिक्षकों और संघ जिलाध्यक्ष उदयशंकर शुक्ल ने तहसीलदार से यह भी कहा कि यदि गड़बड़ी ठीक नहीं होगी तो सोमवार से पूरे जनपद के शिक्षक हर्षा के समक्ष आकर और भी प्रस्तावों के साथ चर्चा करेंगे। बलकृष्ण ओझा, ओमकार उपाध्याय, हरेंद्र यादव, सतीश शंकर शुक्ला, राजीव पाण्डेय, शैलेश प्रकाश सिंह, सुधीर तिवारी, अखिलेश पाण्डेय, विनोद यादव, रवींद्रनाथ, सुनील पाण्डेय, लालेंद्र कुमार, वैभव कर्नौजिया, राम यादव, कल्पनाथ, जनार्दन शुक्ला, मदन गोपाल पाण्डेय, राहुल सिंह मुरारी पर दिवाकर सिंह, राजकुमार, राजेश कुमार, स्कंद मिश्रा, विकास पाण्डेय, संतोष शुक्ला, संतोष सिंह, नरेंद्र यादव, अमोघी तिवारी, विनोद कुमार, प्रमोद तिवारी, रामसगर वर्मा, विकास मिश्रा, विकास द्विवेदी, विकास मिश्रा, शैलेश यादव, नितेश प्रसाद, मोलानाथ, शैलेश नरिंदी देवी, संध्या पाण्डेय, नीलम, हनुमान दुबे सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे।

## युवा भारती संगठन ने डाक्टर पर लगाये गंभीर आरोप: जांच के साथ निलम्बन की मांग

भारतीय बस्ती संवाददाता- बस्ती। युवा भारती संगठन के अध्यक्ष और भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार के पूर्व सदस्य रायच साहलकार समिति डॉ. लवकुश पटेल ने मुख्य चिकित्साधीक्षक बस्ती को पत्र देकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हर्षा में तैनात चिकित्सक डॉ. नंदलाल यादव की घोर लापरवाही पर अमानवीय व्यवहार को लेकर कानूनी कार्यवाई और निलम्बन की मांग किया है।

## मरीजों के साथ अमानवीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं-डॉ. लवकुश पटेल

युवा भारती संगठन ने मांग किया है कि संबंधित चिकित्सक डॉ. नंदलाल यादव को तत्काल प्रभाव से निरोधित करने के साथ ही प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए। संगठन ने भी भी कहा है कि यदि तैनात डॉ. नंदलाल यादव प्रकरण में ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो इस मामले को उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाण्डेय को अस्पताल लाए जाने के उपरांत संबंधित चिकित्सक डॉ. नंदलाल यादव के बाद अपने कर्तव्यों से विमुख होकर ड्यूटी के दौरान ही मुख्य गेट के बाहर स्थित जनता मेडिकल स्टोर पर बैठकर कार्य करने लगे। यह अवैतन आपत्तिका एवं निन्दनीय है। यह न केवल सेवा निषमता का उल्लंघन है, बल्कि मरीजों के अधिकारों के

व्यतिरीक्यता के साथ निम्नलिखित का जनता मेडिकल स्टोर पर बैठना समाविष्ट रूप से अर्थ सांगठन एवं कर्मियों/स्वास्थ्य का संकेत है, जिससे गंभीर मरीजों को आर्थिक शोषण किया जा रहा है और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

## स्वतंत्र अभिव्यक्ति, सशक्तिकरण सराहनीय पहल-संजय कुमार शुक्ल

भारतीय बस्ती संवाददाता- बस्ती। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत मिशन नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत शनिवार को लड़कियों के लिए नि:शुल्क शिक्षण एवं एक दिवसीय संगोष्ठी एवं वर्कशॉप का आयोजन नवगुरुकुल संस्था बरगकुल एवं डाक्टर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया।



## नारी सशक्तिकरण संगोष्ठी, वर्कशॉप में दिया सदेश

गतिविधियां सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया गया। डाक्टर प्राचाय ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसंधानों के संकल्प क्रियान्वयन के लिए यह समर कई बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा कि शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों की संशोधन कक्षा प्रशिक्षण के संदर्भ में डाक्टर ने स्वतंत्र अभिव्यक्ति और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संयुक्त की गई कृषि व्यापक एवं सराहनीय पहल है। इस समर और और सशक्तिकरण के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के मिशन शक्ति के नूतन उद्देश्यों को साकार कर रहा है, जिसका लक्ष्य महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान के क्षेत्र में सशक्त बनाना है। प्राचाय के मार्गदर्शन एवं संकल्प कार्यक्रम को सफल रूप देने में नोबल प्रकाश डॉ गोविंद, कल्याण पाण्डेय, वर्षा पटेल, वंदना चौधरी, अयोधनी, हनुमान आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर अमन सेन, शशिधर शनिवादी, नवनीत, रमकान्त, डीएलएड प्रशिक्षु आनंद, प्रमोद मिश्रा, अरुण, सीरम, विजय कुमार, सिद्धांत, अम्बिका आदि ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया।

## बनकटी में 31.83 करोड़ के लेबर बजट पर लगी मुहर, मनरेगा से रोजगार बढ़ाने पर जोर

भारतीय बस्ती संवाददाता- बनकटी। (बस्ती) विकास खंड बनकटी के ब्लॉक समारंग में शनिवार को क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित हुई। बैठक ब्लॉक प्रमुख मेवाती देवी की सहमति से प्रमुख प्रतिनिधि रामायण रघुनाथ सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा के साथ मनरेगा के तहत वर्ष 2026-27 के लिए 31 करोड़ 83 लाख रुपये के लेबर बजट को संशोधित से मंजूरी दी गई। बैठक में मनरेगा के माध्यम से अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा विकास कार्यों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से संचालित करने पर विशेष जोर दिया गया। जम्मेदारियों और अधिकारिताओं ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आयवृद्धि सुनिश्चित के विकास कार्यक्रमों को प्रभावकारी रूप से निष्पादित किया जाए। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण, बांध विकास एवं पुर्नवास, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना



पहुंचाने के लिए सभी विभाग समन्वय करके कार्य करें। वहीं जिला पंचायत सदस्य सुरेन्द्र कुमार तिवारी, सत्यनारायण शुक्ल, जगदीश प्रसाद शुक्ल, अरविंद प्रसाद प्रतिनिधि नगर पंचायत, रवि चंद्र पाण्डेय, ओमप्रकाश शुक्ल, मनमोहन तिवारी, अरुण कुमार पाण्डेय, ब्रजेश शर्मा तथा डॉ. राजेश कुमार ने जनदूरों को नियमित रोजगार उपलब्ध कराने और विकास कार्यों में तेजी लाने पर बल दिया। बैठक में रमेश अग्रहरी, सुनील कुमार कर्नौजिया, अंकित पाण्डेय, ब्रजेश चौधरी, सुजीत सिंह, रविन्द्र सिंह, प्रमोद राम कलेश कर्नौजिया, राजेश चौधरी, राम किरण चौधरी, मो. अली, मो. सोमेश सक्सेना सभी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ डाक्टर प्राचाय संजय कुमार शुक्ल ने ही सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम में नवगुरुकुल संस्था के मंत्री राम अशोषी चौहान, विनोद शर्मा एवं प्रमोद कुमार ने डीएलएड प्रशिक्षुओं को शिक्षा नीति 2020 के अनुसंधानों को निष्पक्ष शक्तिकरण विषय से संबंधित मिश्रण शिक्षा प्रक्रिया के बारे में बताया और उसके उपलब्ध पहल की गई। जिसमें डाक्टर के 42 बच्चे फर्स्ट राउंड में क्वालिफाइड हुए। यही शिक्षा अब नेक्टर राउंड की प्रतीक्षा में प्रशिक्षण करेगे। साथ ही आरना थिएटर एवं एक्टिंग स्टूडियो के संचालन में नाटक, मूवी के नूतन रूप को आध्यात्मिक प्रस्तुतिकरण, अभिनय, गीत, नृत्य, व सांस्कृतिक

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता" -वेडेल फिलिपा

# भारतीय बस्ती

बस्ती 24 मई 2026 रविवार

## सम्पादकीय

### आसमान से बरसती आग

हाल के दिनों में आसमान से बरसती आग से देश में जन-जीवन बुरी तरह झुलस रहा है। रोज तापमान बढ़ने में जो रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। ये असहनीय तापमान केवल स्वास्थ्य की चुनौती मात्र नहीं है, बल्कि एक आर्थिक संकट भी है। देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक भीषण गर्मी में काम करने को मजबूर हैं। यदि वे ऐसा न करें तो उनके सामने आजीविका का संकट पैदा हो जाता है। रकूल-कालेज तो लू के दौरान बंद किए जा सकते हैं, सरकारी व गैर सरकारी दफ्तरों में काम के घंटों में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन खेत में काम करने वाले खेतिहर मजदूर व निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को तो तपती दोपहर व लू के बीच काम करने को मजबूर होना पड़ता है। दरअसल, लू की मार जहां शारीरिक है, वहीं आर्थिक भी। लगातार बढ़ते तापमान से लोगों की आजीविका और श्रम उत्पादकता पर बुरा असर पड़ रहा है। इस संकट को हाल के दिनों में हुई इंधन की कीमतों की वृद्धि और महंगाई ने और बढ़ा दिया है। लोगों को सीमित संसाधनों में जीवन यापन को मजबूर होना पड़ रहा है। विडंबना यह है कि इस संकट का सबसे घातक प्रभाव उस तबके को सहन करना पड़ता है जो रोज कुआ खोदकर पानी पीने को बाध्य है। एक दिन की कमाई से ही रात को उसके घर का चूल्हा जलता है। लू के निशाने पर वे अनौपचारिक श्रमिक हैं जो भारतीय आर्थिक की रीढ़ हैं। सही मायनों में लू के खिलाफ लड़ाई को अब केवल एक मौसमी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या ही नहीं माना जा सकता है। धीरे-धीरे यह एक गंभीर आर्थिक चुनौती भी बनी है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस बाबत चेतावत रहे हैं। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अनुमान लगाया था कि लू से उपजे हालात से भारत को सौ अरब डॉलर का नुकसान हुआ था।

इससे पहले वर्ष 2022 में विश्व बैंक ने चेतावनी दी थी कि भारत का तीन-चौथाई श्रमिक वर्ग लू से प्रभावित क्षेत्रों में काम करने को मजबूर है। अनुमान है कि लू के तनाव के कारण होने वाली विश्वव्यापी नौकरियों की कमी में भारत की हिस्सेदारी आधी हो सकती है। दरअसल, भारत में सबसे अधिक जोखिम वाले समूहों में निर्माण श्रमिक, खेतिहर श्रमिक, किसान, स्ट्रीट वेंडर और इलेक्ट्रिक एजेंट शामिल हैं। हालांकि, समय-समय पर केंद्र व राज्य सरकारों ने कार्य समय का पुनर्निर्धारण, छायादार विश्राम क्षेत्र बनाने, जलपान सुविधा, सुरक्षात्मक कपड़े और स्वास्थ्य निगरानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है। लेकिन फिर भी संकट के दायरे को देखते हुए ये उपाय नाकाफी हैं। देखा जाए तो फिलहाल भारत में गर्मी के संकट से मुकाबले के लिये बनायी गई योजनाएं काफी हद तक अस्थायी रूप से राहत देने वाली हैं। वक्त की मांग है कि भीषण गर्मी वाले महीनों के लिये तत्काल व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार किया जाए। ऐसा तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो लू चलने के दौरान सुरक्षित कार्य परिस्थितियों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करे। इस साल के आरंभ में वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि भीषण गर्मी के दौरान चलने वाली लू को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अधिसूचित आपदाओं की सूची में शामिल किया जाए। निस्संदेह, इस वर्गीकरण से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से मिलने वाले धन का उपयोग लोगों को राहत और सहायता प्रदान करने में मदद देगा। इसके अलावा लू के दौरान कई अन्य नकारात्मक प्रभाव भी देखने में आते हैं। मसलन इस समय विजली व पानी की खपत अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है। इससे निबटने के लिये मजबूत और सक्रिय तंत्र विकसित करने की जरूरत है। निर्विवाद रूप से देश के नीति-निर्माताओं और अन्य हितधारकों के सामने इस संकट से मुकाबले के लिये स्पष्ट विकल्प मौजूद हैं। केंद्र व राज्य सरकारों को चाहिए कि समय रहते निर्णायक रूप से अनुकूलन का तंत्र विकसित करें। यदि समय रहते इस दिशा में कदम नहीं उठाया गया तो भविष्य में अधिक मानवीय क्षति व आर्थिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।

# समझना होगा युवा मन की पीड़ा और आक्रोश



-विश्वनाथ सचदेव-

पिछले पच्चीस सालों में सी से अधिक आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। 'फ्री स्पीच कैंडिडेट' के अनुसार भारत में पिछले दो दशकों में पचास से अधिक पत्रकार पेशेवर कार्यों के कारण मारे जा चुके हैं। ऐसे लोगों को जब कोई कॉन्कोरव या परजीवी कहे तो दुख भी होना चाहिए और गुस्सा भी आना चाहिए।

पिछले कुछ दिनों से अचानक कॉन्कोरव यानी तितवट्ट देश में घर्वा का विषय बन गया है। नही कॉन्कोरव ने कुछ नया नहीं किया है। हुआ यह है कि देश की सर्वोच्च अदालत के मुखिया ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अपनी अलिखित टिप्पणी में कॉन्कोरव का नाम लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि देशभर में घर्वा चल पड़ी है। मामला एक वकील द्वारा 'वरिष्ठ वकील' कहलाये जाने की मांग को उठाये जाने का था। उसकी मांग को अनुचित बताते हुए मुख्य न्यायाधीश महोदय ने उस जैसे वकीलों की तुलना कॉन्कोरव से कर दी। उन्होंने कहा, कुछ बेरोजगार युवा कॉन्कोरव जैसे होते हैं जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट आदि बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं।



स्पष्ट है उन्हें वह वकील महोदय भी सिस्टम पर हमला करने वाले लगे होंगे। मुख्य न्यायाधीश तो यह टिप्पणी करके चुप हो गये थे, पर इस टिप्पणी को लेकर देश बोलने लगा। बेरोजगारों, एक्टिविस्टों, मीडिया कर्मियों, ने मुख्य न्यायाधीश की इस टिप्पणी को अनुचित ही नहीं, शर्मनाक भी बताया। सचमुच, यह समझना आसान नहीं है कि देश के सर्वोच्च पदा में से एक पर बैठने वाला व्यक्ति देश के युवाओं की तुलना कॉन्कोरव जैसे जीव कैसे कर सकता है!

बात जब बढ़ने लगी तो न्यायाधीश महोदय ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए यह कहा कि उनकी बात को अनुचित रूप से सामने रखा जा रहा है, उनका मुख्य निशाना तो उन लोगों पर था जो फर्जी डिग्रियां से कानूनी पेशे में आ जाते हैं और सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। जहां तक भारत के युवाओं का सवाल है, उन्हें तो वह विवेकित भारत का स्तंभ मानते हैं। मुख्य न्यायाधीश महोदय ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी कहा कि उन्हें

युवाओं की वर्तमान और भविष्य की क्षमता पर नर्व हैं। होना तो यह चाहिए था कि इस स्पष्टीकरण के बाद विवाद यही समाप्त हो जाता, पर हुआ नहीं। मुख्य न्यायाधीश द्वारा युवाओं, एक्टिविस्टों, मीडिया कर्मियों की तुलना कॉन्कोरव से किया जाना लोगों को रास नहीं आ रहा। मुख्य न्यायाधीश ने सिर्फ कॉन्कोरव ही नहीं कहा, उनके लिए 'परजीवी' शब्द का इस्तेमाल भी किया। यदि यह विशेषण युवा भारत को आहत कर रहा है तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता।

मुख्य न्यायाधीश चाहते तो कॉन्कोरव या परजीवी जैसे शब्दों के अनुचित उपयोग पर धना मान सकते थे। क्षमता ही जमीनी तो कम से कम खेत तो व्यक्त कर ही सकते थे। उनका ऐसा करना एक उदाहरण होता उन सबके लिए जो सार्वजनिक व्यवहार में इस तरह के शब्द अक्सर बोल जाते हैं। स्वार्थ शब्दों का ही नहीं है, इनके पीछे भी मानसिकता है। इनके दे युवाओं को कॉन्कोरव या परजीवी कहने की इस मानसिकता

को समझना जरूरी है। किसी गलत काम करने के लिए एकिलो को सांप या बिच्छू भी कहा जा सकता था। पर जाने-अनजाने मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कॉन्कोरव शब्द का इस्तेमाल किया। कॉन्कोरव शब्द अपने आप में एक लंबी कहानी और प्रसूति को उजागर करता है। आज जिसे हम कॉन्कोरव कहते हैं, उसका जन्म शाब्द जुलासिक काल में हुआ था। आज से 320 मिलियन साल पूर्व। यह शाब्द अकेला जीव है जो तीन करोड़ सालों से अधिक समय से धरती पर है और कहते हैं इसका अस्तित्व कभी समाप्त ही नहीं होगा। न्यूसियर युद्ध के बाद भी कॉन्कोरव के धरती पर बने रहने की बात भी वैज्ञानिक कहते रहते हैं!

महान जर्मन कथाकार फ्रांज काफ़्का की कहानी 'दि मेटामॉर्फोसिस' में कॉन्कोरव का सीधा वर्णन तो नहीं किया गया, पर कहानी का मुख्य पात्र ग्रेगर साम्सा एक खतरनाक कीड़े में बदल जाता है। काफ़्का ने इसके लिए एक जर्मन

शब्द 'अनजैसिफर' का इस्तेमाल किया है, इसका अर्थ 'गदा कीड़ा' या 'बीमारी फैलाने वाला जीव' होता है। वस्तुतः कहानी में एक जीव का इस कीड़े के रूप में कायांतरण होता है। जिसकी मृत्यु उसके परिवार के लिए महत्वहीन होने की अनुभूति थी। आप चाहें तो इस 'अनजैसिफर' को घृणा करने योग्य कीड़े के रूप में देख सकते हैं जो तिजलिजा हेंग जो गंदे गीले माहलों में पलता है जो परजीवी हैट्ट और जो किसी काम का नहीं रहा है। जब हम किसी को कॉन्कोरव या तिलचट्टा कहते हैं तो वस्तुतः हम उसे एक ऐसे जीव के रूप में देख रहे होते हैं जो किसी काम का नहीं है, जो अंधेरे में जीता है, जो छिपकर वार करता है, जो परजीवी है!

आज यदि देश के मुख्य न्यायाधीश द्वारा युवाओं को कॉन्कोरव कहे जाने पर आपाति है तो उसके पीछे इस मानसिकता के तनकार की प्रसूति है जो परजीवी को एक गली के रूप में देखती है। सांप-बिच्छू जैसे जीवों के विपरीत कॉन्कोरव को छिपे हुए संक्रमण और उपेक्षित जहाजे पर रहने से जोड़ा जाता है। उसका रिजलिजिपान एक अजीब-बौद्ध अनुभूति उत्पन्न करता है।

देश के बेरोजगारों को परजीवी मानने-कहने का मतलब देश के एक करोड़ से अधिक युवाओं को नाकारा बतलाना है। उनका अपराध 'युवा पाप' यह है कि हमारी व्यवस्था उन्हें रोजगार नहीं दे पायी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम आयोग और मानव विकास संस्थान के एक सर्वेक्षण के अनुसार वंशह से उन्तीस वर्ष की आयु वर्ग में आने वाले भारतीय युवाओं में 63 प्रतिशत बेरोजगार हैं। इन बेरोजगारों में से 67 प्रतिशत युवा स्वतंत्र हैं। आंकड़े यह भी बताते हैं कि सन 2000 की तुलना में आज

यह संख्या दुगुनी हो चुकी है। तब 35 प्रतिशत युवा बेरोजगार थे, आज 65 प्रतिशत से अधिक युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। आखिर क्यों? इस विषय के लिए कौन जिम्मेदार हैं? किसका दायित्व है इन युवाओं को रोजगार देना? फिर, जब इन युवाओं में से कुछ आर टी आई कार्यकर्ता बन जाते हैं, मीडियाकर्मी के रूप में काम करने लगते हैं या व्यवस्था के प्रति अपना गुस्सा अभिव्यक्त करते हैं तो उन्हें परजीवी कॉन्कोरव कहा जाता है! आखिर क्यों?

किसी को कॉन्कोरव कहने की इस मानसिकता के पीछे सिर्फ व्यक्तिगत आक्रोश नहीं होता। देश का मुख्य न्यायाधीश जब ऐसे शब्दों से अपना आक्रोश या अपनी पीड़ा व्यक्त करता है तो हमला व्यक्ति या स्थिति पर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा पर होता है। सन 2005 में देश में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, तब से लेकर आज तक न जाने कितनी बार सरकार से उनकी संस्था मानी गयी जो इस कार्य को करते हुए मारे गये, पर यह आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं हुए। गैर सरकारी संगठनों के अनुमान के अनुसार पिछले पच्चीस सालों में सी से अधिक आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। फ्री स्पीच कैंडिडेट के अनुसार भारत में पिछले दो दशकों में पचास से अधिक पत्रकार पेशेवर कार्यों के कारण मारे जा चुके हैं। ऐसे लोगों को जब कोई कॉन्कोरव या परजीवी कहे तो दुख भी होना चाहिए और गुस्सा भी आना चाहिए। यह एक अक्षी बाँट है कि आज यह पीड़ा और क्षोभ उपान कर सामने आ रहा है। इस पीड़ा को समझने की आवश्यकता है, इसकी उपेक्षा करने की नहीं।

-लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

## जनस्वास्थ्य पर बाजार का बढ़ता कब्जा



-डॉ. प्रियंका सौरभ-

भारत जैसे विशाल और विविध तापुर्ण देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य केवल विकरिस्ता सेवा का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का विषय भी है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों के स्वास्थ्य स्तर से मापी जाती है। यदि समाज का बड़ा हिस्सा उपचार, दवाव्यो, पोषण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाए, तो आर्थिक विकास के दावे खोखले साबित होते हैं। दुर्भाग्य से पिछले कुछ दशकों में भारत सहित विश्व के अनेक देशों में स्वास्थ्य क्षेत्र का तेजी से बाजारीकरण हुआ है। स्वास्थ्य सेवा, जो मूलतः मानव अधिकार माननी जानी चाहिए थी, धीरे-धीरे लाभ कमाने वाले उद्योग में बदलती चली गई। निजी अस्पतालों, महंगी दवाओं, बीमा-आधारित उपचार और कॉन्पोसेट विकरिस्ता व्यवस्था ने आम नागरिक, विशेषकर ग्रामीण और श्रामीण वर्ग, को स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर कर दिया है। ऐसे समय में भारतीय राज्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करे और जमीनी स्तर तक उद्योग की पूर्ण सुनिश्चित करे।



सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए सबसे पहला राज्य को प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना होगा। भारत के गाँवों और छोटे कस्बों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। लेकिन अधिकांश केंद्रों में डॉक्टरों की कमी, दवाव्यो का अभाव, खराब भवन और उपकरणों की कमी जैसी समस्याएँ बनी रहती हैं। सरकार को स्वास्थ्य बजट में पर्याप्त वृद्धि करके इन स्थितियों को अनुचित सुविधाओं से लैस करना चाहिए। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नियमित डॉक्टर, प्रशिक्षित नर्स, लैब सुविधाएँ और आवश्यक दवाव्यो उपलब्ध कराना अनिवार्य होना चाहिए। यदि प्राथमिक स्तर पर ही लोगों की पर्याप्त और उपचार चलाए जायें, तो बड़े अस्पतालों पर दबाव कम होगा और नर्बल लोगों को शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा।

इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण भी आवश्यक है। केवल निजी अस्पतालों पर निर्भर रहने से दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को भारी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकारों को पंचायत स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना चाहिए। आशा कार्यकर्ता, आँगनवाड़ी सेनाएँ और सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को मजबूत करने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए निररुच्छ उपकरणों का निर्माण और प्रसारण आवश्यक है। स्वास्थ्य सेवाओं को पर्याप्त महत्व नहीं मिलता। राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ केवल उपचार नहीं, बल्कि रोकथाम, पोषण और प्राथमिक देखभाल को भी शामिल करें।

अधिकार चिकित्सक शहरी क्षेत्रों में कार्य करना पसंद करते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को ग्रामीण सेवा को प्रोत्साहित करने वाली नीतियाँ बनानी चाहिए। मंडेकल छात्रों के लिए ग्रामीण सेवा अनिवार्य करना, बेहतर वेतन, आवास और सुरक्षा सुविधाएँ देना तथा स्थानीय युवाओं को चिकित्सा शिक्षा में अवसर प्रदान करना उपयोगी कदम हो सकते हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय से जुड़े डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी तैयार किए जाएँ, तो स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तारता और विश्वसनीयता दोनों बढ़ेंगी।

सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवारक स्वास्थ्य देखभाल को भी प्राथमिकता देनी होगी। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी रोग होने के बाद उपचार पर अधिक केंद्रित है, जबकि स्वच्छता, पोषण, टीकाकरण और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश अस्वाभाविक कम है। यदि राज्य स्वच्छ पेयजल, पोषण कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण जैसी सुविधाओं को मजबूत करे, तो अनेक बीमारियों को प्राथमिक स्तर पर ही रोक जा सकता है। यह न केवल लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर आर्थिक बोझ भी कम करेगा।

राज्य को निजी स्वास्थ्य क्षेत्र के नियंत्रण में भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। निजी अस्पतालों की मनमानी फीस, अनावश्यक चार्ज और व्यापक विपणन शोषण आम समस्या हैं चुकी हैं। कई बार मरीजों की मजबूती को लाभ कमाने के सन्धान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सरकार को एक मजबूत नियामक ढांचा विकसित करना चाहिए जो उपचार, चिकित्सा, दवाव्यो की कीमत और चिकित्सा नैतिकता की निगरानी कर सके। स्वास्थ्य सेवा को केवल बाजार के मरसे पीछे छोड़ने लोकतांत्रिक राज्य की जिम्मेदारी से पीछे हटने जैसा होगा।

## जानलेवा होती गर्मी का दुष्प्रभाव



-कमलेश पाण्डेय-

विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सौजन 27 अप्रैल और 19 मई को ऐसे दिन रहे, जब धरती के सबसे ज्यादा 60 शहरों में गर्मी भारत के थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट हमें चेताती है कि देश के 50 से ज्यादा शहरों में भीषण गर्मी का खतरा अधिकतर से लेकर बेहतर अधिकतर के स्तर तक पहुंच चुका है। हमारे देश का राजनीतिक तापमान तो वर्षभर उच्च रहता आया है और चुनौती इलाकों में इसके वैचारिक हिट स्टूडों के सिस्टम का झुलसना स्वाभाविक माना जाता है। लेकिन जब मई-जून के महीने में मौसमी तापमान जानलेवा स्तर तक खतरनाक रूप से बढ़ता जाता है तो लोग बग परेशान हो उठते हैं। फिर अपनी राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक गलतियों पर पछाया को अत्यांत कुछ नहीं मिलता, क्योंकि विकास के नाम पर आधुनिक भारतीय संस्था विनाश की ओर बढ़ती चली जा रही है और परिणामी शिक्षा प्राप्त करने हुए हुकराम तमशाहीन बने बैठे हैं, क्योंकि बेहतर आपदा को अवसरों में बदलकर अपनी कमाई बढ़ाने का धंधा उन्होंने सीख लिया है। कर्मक अपवाद भी होयें, लेकिन अल्पमत में, जिनकी लोकतंत्र में कम कदर होती आ है।

वहीं, भारत में बढ़ती खतरनाक गर्मी केवल 'मौसमी बदलाव' नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन, तेजी से शहरीकरण, जंगलों की कटाई और प्रदूषण का संयुक्त परिणाम बन चुकी है। हाल के वर्षों में उत्तर भारत, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य भारत में 46 बृहत् २ तक तापमान दर्ज हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स दर्शाते हैं कि भारत में 2015 से 2020 के दरम्यान लू वाले दिनों का औसत 7.4 दिन से बढ़कर 32.2 दिन हो चुका है, और यह लगातार बढ़ रहा है। इसका गहरा दुष्प्रभाव हमारे संसत और अर्थव्यवस्था में भी पड़ने के आधार पर है। हमारे शहरों पर संकट के बालन मंडारने लगे हैं, क्योंकि वो अंधाधुंध विकास की होड़ में अपनी हथियारी उजाड़कर उन्हें कभीचि नहीं देते हैं। मईवर्ष तकते जा रहे हैं। जिहाज, भारत में गर्मी और सूखे का शिकार बारा रेकॉर्ड बना रही है। जिहाजक बारा रेकॉर्ड यह है कि दिन तो तापते ही हैं, अब रातें भी तपने लगी हैं और शहत देते बाली नहीं रहते। इस 20 मई के दिनांक में कई महीने में 13 लसाल की सतसे गर्म रात देखी, जब न्यूनतम तापमान सामान्य से 5-7 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। 21 मई को स्थिति उससे भी ज्यादा बुरी हुई। इस शहर ही आइलैंड में तटीय होयें। इससे ही है। उत्तर भारत से लेकर मध्य व भारत तक, ज्यादातर शहरों में औसत तापमान सामान्य से 3-5 डिग्री सेल्सियस ऊपर चर रहा है। कहीं कहीं तो पिछले 14-15 वर्षों के रिकॉर्डों तक चूके हैं। कोरे में खाज आईलैंड इफेक्टव अेल रहे हैं। यह है फिलहाल भारत के संकट



